



लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुगदाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,गौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजाबाद,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रससित

वर्ष : 14 अंक 344
लखनऊ, गुरुवार, 03 जुलाई 2025
पृष्ठ: 8
मूल्य : 2.00


संक्षिप्त

विदेशी निर्भरता से झुक रही है किसान की रीढ़ : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि किसान के लिए खाद जैसी जरूरी वस्तु विदेश पर निर्भता बढ़ रही है और इसे कम करने के प्रयास नहीं हो रहे हैं,इसलिए किसान की रीढ़ लगातार झुक रही है। श्री गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, झ्रभारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन आज यही रीढ़ विदेशी निर्भरता के कारण झुकती जा रही है। भारत 80 प्रतिशत स्पेशियलटी फर्टिलाइज़र चीन से मंगाता है और अब चीन ने सप्लाई रोक दी है। यह पहली बार नहीं है - यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी खादों की कमी से देश भर का किसान अब तक जूझ ही रहा है कि अब स्पेशियल्टी खाद का 'चीनी संकट' मंडराने लगा।

हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 10 मरे, 34 लापता

शिमला/मंडी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भूस्खलन और बादल फटने की कई घटनाओं में मंडी जिले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है जबकि 34 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा अभियान केन्द्र ने यह जानकारी दी है। पिछले तीन वर्षों से राज्य में लगातार कहर बरपा रहे मानसून के कारण एक बार फिर से मंडी के कई क्षेत्रों, खासकर करसोग, थुनाग, पधर और गोहर उप-मंडलों में तबाही मची हुयी है। इस बीच 20 जून से 1 जुलाई के बीच राज्य में मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग 90 लोगों की मौत या लापता होने की सूचना है। बुधवार सुबह 8 बजे जारी 32 घंटे की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार संबंधी विभिन्न हिस्सों से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और आधिकारिक तौर पर 34 लोगों के लापता होने की सूचना है। कई लोगों के मलबे में दबे होने या कंकड़ कंकड़ आई बाढ़ में बह जाने की आशंका है।

ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय बदला, अब 8 घंटे पहले तैयार होगी सूची

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण सूची (चार्ट) तैयार करने के नियमों में बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार, अब यात्रियों को अपने यात्रा की स्थिति पहले से पता चल सकेगी, जिससे उन्हें समय रहते सीट की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब विभिन्न समय पर चलने वाली ट्रेनों के लिए पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भव्यता से मनाया अपना स्थापना दिवस

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अवध प्रांत ने 2 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया इस अवसर पर न्यास ने समाज में चरित्रवान नागरिकों के निर्माण हेतु चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास विषय पर एक विमर्श का आयोजन लखनऊ के स्कार्पियो क्लब परिसर में स्थित धर्म भारती राष्ट्रीय शान्ति एवं सशत विकास विद्या पीठ में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ विद्या विन्हु सिंह और मुख्य वक्ता चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी आचार्य स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो कीर्ति नारायण ने किया.

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अवध

प्रांत के संयोजक प्रमिल द्विवेदी ने बताया कि व्यक्तित्व का विकास प्रक्रिया है चरित्र निर्माण उसका परिणाम, सम्पूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है व्यक्तित्व को गढ़ना शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का स्थापना दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारत में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, इसके संस्थापक दीनानाथ बत्रा थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और विद्या भारती के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का आधारभूत विषय हैं, क्योंकि मूल्यपरक शिक्षा के अभाव में मनुष्य के चरित्र का निर्माण एवं



व्यक्तित्व का समग्र विकास कठिन कार्य है। सही अर्थों में शिक्षा में भारतीयता तभी आ सकती है, जब उसमें मूल्यबोध का समावेश हो। इसी को ध्यान में रखकर 'चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास' विषय को न्यास ने आगे बढ़ाया है। इस दृष्टि से छत्रंचकोश की संकल्पना'' को केन्द्र में रखकर न्यास ने विद्यालय



स्तर पर पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार की हैं और निरंतर इस विषय की कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। प्रमिल द्विवेदी ने आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार एवं समाज दोनों के संयुक्त प्रयास से ही किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन संभव है,न्यास के द्वारा प्रारम्भ किये गए इन



प्रयासों में आप भी तन मन धन से अपनी आहुति प्रदान करें। मुख्य वक्ता वचिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी आचार्य स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अवध प्रांत द्वारा चरित्र निर्माण जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श आयोजित करने की पहल सराहनीय है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चरित्र

● चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास विषय पर हुआ विमर्श

निर्माण के क्षेत्र में काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्यों और अच्छे चरित्र का विकास करना है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मतत्व का व्यक्त रूप है व्यक्ति, सृष्टि पर जीवों में श्रेष्ठ व्यक्त रूप मनुष्य है व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व. इनके दो हिस्से हैं आंतरिक एवं बाह्य, व्यक्तित्व को समझना है तो पञ्च कोष(अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और

आनंदमय कोष) को समझना होगा. पाँचों कोषों का विकास यानि व्यक्तित्व का समग्र विकास इस हेतु कुछ करणीय बिन्दु है जैसे मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु अध्ययन,स्वाध्याय,पढाई कार्य शुरू करने से पूर्व तीन बार १?का एवं एक मिनट मौन रखें । यह न्यास शिक्षा में भारतीयता को पुन: स्थापित करने और मानव चेतना के विकास भी जोर देता है। छात्रों में दयाभाव और सिंह जैसा साहस पैदा हो,छात्र संयमित बनें तथा प्रत्येक छात्र को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए।व्यक्ति नियमित जो भी कार्य करता है, वह उसकी आदत बन जाती है. लम्बे समय तक आदत रहने से वह उसका स्वाभाव बन जाता है वही चरित्र कहलाता है अच्छी आदतें ही मूल्य हैं हमारे शैक्षिक संस्थाओं एवं

परिवारों में अच्छी आदतों (मूल्य शिक्षा) के द्वारा व्यक्ति सदाचारी बनेगा, उनके आधार पर वह नैतिकता के रास्ते पर चलने हेतु सक्षम होगा जिससे समाज में चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होगा। कार्यक्रम का संचालन दीप नारायण पांडेय ने किया तथा योगाचार्य डॉ सत्येन्द्र सिंह ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का भी जोर देता है। छात्रों में दयाभाव और सिंह जैसा साहस पैदा हो,छात्र संयमित बनें तथा प्रत्येक छात्र को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए।व्यक्ति नियमित जो भी कार्य करता है, वह उसकी आदत बन जाती है. लम्बे समय तक आदत रहने से वह उसका स्वाभाव बन जाता है वही चरित्र कहलाता है अच्छी आदतें ही मूल्य हैं हमारे शैक्षिक संस्थाओं एवं



आज की बैठक के बारे में उन्हें सुबह तक कोई पुष्टि नहीं की गयी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आयोग आज शाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकता है। इस बैठक के लिए इस पार्टी ने अपनी सहमति की पुष्टि कर दी है। इस बीच आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों की ओर से आयोग को 30 जून और दो जुलाई को मेल भेजने वाले उम्मेर होय को आज एक मेल करके कहा है, झ्रभविष्य में, राजनीतिक दलों और आयोग के बीच

किसी भी अनधिकृत संचार को रोकने के लिए, आपको उस राजनीतिक दल के प्रमुख से वैध प्राधिकरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। आयोग के सचिव ने श्री होदा को लिखा है, मुझे यह कहना का निर्देश हुआ है कि आपके 30 जून 2025 के ईमेल के अनुसार, उल्लिखित राजनीतिक दलों से प्राधिकरण का कोई सबूत न होने के बावजूद, आयोग ने संबंधित राजनीतिक दलों को 02 जुलाई 2025 को शाम 05:00 बजे का समय दिया था और पार्टियों के प्रमुखों से एक अधिकृत व्यक्ति के साथ उक्त बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि मांगी थी। इस मेल में कहा गया है कि अभी तक केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव ने ही इस संबंध में पुष्टि की है।

शीघ्र और पारदर्शी हो जन समस्याओं का समाधान : योगी

● जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं, निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। ध्यान से सबकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता और



पारदर्शिता शीघ्रता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने

जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सबको आश्वास किया कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश देने के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने हुए

उसकी सहायता की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वास दिया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इमर्जेंसी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए।

● प्रधानमंत्री मोदी का पांच देशों की यात्रा पर प्रस्थान पूर्व वक्तव्य

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के लिए प्रस्थान करने से पहले जारी वक्तव्य में कहा, ‘‘मेरी इन देशों की यात्रा से वैश्विक दक्षिण में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे।’’ प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है, ‘‘ आज, मैं

● प्रधानमंत्री मोदी का पांच देशों की यात्रा पर प्रस्थान पूर्व वक्तव्य

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के लिए प्रस्थान करने से पहले जारी वक्तव्य में कहा, ‘‘मेरी इन देशों की यात्रा से वैश्विक दक्षिण में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत होंगे।’’ प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है, ‘‘ आज, मैं



02 से 09 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की पांच देशों की यात्रा पर जा रहा हूं। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर मैं 02-03 जुलाई को घाना जाऊंगा। घाना वैश्विक दक्षिण में एक मूल्यवान भागीदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं अपने

भारत ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं 06-07 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। एक संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। साथ मिलकर, हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयास करते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान, मैं कई विश्व नेताओं से भी मिलूंगा। मैं एक द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए ब्रासीलिया की यात्रा करूंगा, जो लगभग छह दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा ब्राजील के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और मेरे मित्र, राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्व्वा के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।

यात्रा करूंगा। यह 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और जी-20 में एक करीबी सहयोगी है। मैं राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ अपनी चर्चा का इंतजार कर रहा

हूं, जिनसे मुझे पिछले साल मिलने का सौभाग्य भी मिला था। हम कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों सहित अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

पार्टियों की ओर से अधिकृत व्यक्तियों की चिट्ठी-पत्री पर ही गौर करेगा चुनाव आयोग

एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वह राजनीतिक दलों की ओर से चिट्ठी-पत्री में उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऐसे व्यक्तियों की बात पर ही गौर करेगा जिन्हें दल के प्रमुखों द्वारा आयोग से संपर्क के लिए बाकायदा अधिकृत किया गया होगा। इस बीच आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि विहार में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के विषय में बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी द्वारा दी गयी दोनों अधिकृत मेलों पर को 30 जून को निमंत्रण भेजा गया था। इन मेल में उन्हें आज शाम पांच बजे का समय दिया गया था। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पार्टी की ओर से

आज की बैठक के बारे में उन्हें सुबह तक कोई पुष्टि नहीं की गयी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आयोग आज शाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकता है। इस बैठक के लिए इस पार्टी ने अपनी सहमति की पुष्टि कर दी है। इस बीच आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों की ओर से आयोग को 30 जून और दो जुलाई को मेल भेजने वाले उम्मेर होय को आज एक मेल करके कहा है, झ्रभविष्य में, राजनीतिक दलों और आयोग के बीच

किसी भी अनधिकृत संचार को रोकने के लिए, आपको उस राजनीतिक दल के प्रमुख से वैध प्राधिकरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है जिसका आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। आयोग के सचिव ने श्री होदा को लिखा है, मुझे यह कहना का निर्देश हुआ है कि आपके 30 जून 2025 के ईमेल के अनुसार, उल्लिखित राजनीतिक दलों से प्राधिकरण का कोई सबूत न होने के बावजूद, आयोग ने संबंधित राजनीतिक दलों को 02 जुलाई 2025 को शाम 05:00 बजे का समय दिया था और पार्टियों के प्रमुखों से एक अधिकृत व्यक्ति के साथ उक्त बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि मांगी थी। इस मेल में कहा गया है कि अभी तक केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव ने ही इस संबंध में पुष्टि की है।

क्वाड देशों ने की पहलगाम हमले की कड़ी निंदा

● वाशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह ने संयुक्त रूप से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, स्थिरता और कानून के शासन की रक्षा के लिए अपने साझा संकल्प को दोहराया है। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद जैसे विषयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। क्वाड देशों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को



जल्द न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया गया। आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। म्यांमार संकट पर क्वाड ने युद्धविराम की आवश्यकता दोहराई और आसियान की पांच बिंदु सहमति के कार्यान्वयन का समर्थन किया। म्यांमार भूकंप राहत के लिए

संयुक्त रूप से 3 करोड़ डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की।

वाॅशिंगटन डीसी में आयोजित क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद चीन संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, झ्रहम इस निन्दनीय कृत्य (पहलगाम हमले) के अपराधियों, आयोजकों और वित्तपोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हैं और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य

सभी 75 जिलों में होगा ग्रोथ प्रमोटर व ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, 20% तक बढ़ेगा उत्पादन

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और जैविक कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक दूरगामी योजना तैयार की है। राज्य के सभी 75 जिलों में जल्द ही ग्रोथ प्रमोटर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग शुरू किया जाएगा। पंचगव्य आधारित नवाचार को केंद्र में रखते हुए यह अभियान रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और कृषि सुधार इन तीनों मोर्चों पर ठोस प्रभाव डालेगा।विशेषज्ञों के अनुसार, इससे फसलों की सुरक्षा

● योगी सरकार हर जिले में पंचगव्य आधारित नवाचार से खोलेगी रोजगार के द्वार

सुनिश्चित होगी और उत्पादन में लगभग 20% तक की वृद्धि सम्भावित है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी से बने पंचगव्य उत्पादों के उत्पादन और विपणन को लेकर व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसका कार्यान्वयन जल्द प्रारम्भ किया जाएगा।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने भव्यता से मनाया अपना स्थापना दिवस

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अवध प्रांत ने 2 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया इस अवसर पर न्यास ने समाज में चरित्रवान नागरिकों के निर्माण हेतु चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास विषय पर एक विमर्श का आयोजन लखनऊ के स्कार्पियो क्लब परिसर में स्थित धर्म भारती राष्ट्रीय शान्ति एवं सशत विकास विद्या पीठ में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ विद्या विन्हु सिंह और मुख्य वक्ता चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी आचार्य स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो कीर्ति नारायण ने किया.

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अवध

प्रांत के संयोजक प्रमिल द्विवेदी ने बताया कि व्यक्तित्व का विकास प्रक्रिया है चरित्र निर्माण उसका परिणाम, सम्पूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है व्यक्तित्व को गढ़ना शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का स्थापना दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारत में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, इसके संस्थापक दीनानाथ बत्रा थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और विद्या भारती के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास विषय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का आधारभूत विषय हैं, क्योंकि मूल्यपरक शिक्षा के अभाव में मनुष्य के चरित्र का निर्माण एवं



व्यक्तित्व का समग्र विकास कठिन कार्य है। सही अर्थों में शिक्षा में भारतीयता तभी आ सकती है, जब उसमें मूल्यबोध का समावेश हो। इसी को ध्यान में रखकर 'चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास' विषय को न्यास ने आगे बढ़ाया है। इस दृष्टि से छत्रंचकोश की संकल्पना'' को केन्द्र में रखकर न्यास ने विद्यालय



स्तर पर पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार की हैं और निरंतर इस विषय की कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। प्रमिल द्विवेदी ने आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार एवं समाज दोनों के संयुक्त प्रयास से ही किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन संभव है,न्यास के द्वारा प्रारम्भ किये गए इन



प्रयासों में आप भी तन मन धन से अपनी आहुति प्रदान करें। मुख्य वक्ता वचिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी आचार्य स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अवध प्रांत द्वारा चरित्र निर्माण जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श आयोजित करने की पहल सराहनीय है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चरित्र



निर्माण के क्षेत्र में काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्यों और अच्छे चरित्र का विकास करना है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मतत्व का व्यक्त रूप है व्यक्ति, सृष्टि पर जीवों में श्रेष्ठ व्यक्त रूप मनुष्य है व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व. इनके दो हिस्से हैं आंतरिक एवं बाह्य, व्यक्तित्व को समझना है तो पञ्च कोष(अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और

आनंदमय कोष) को समझना होगा. पाँचों कोषों का विकास यानि व्यक्तित्व का समग्र विकास इस हेतु कुछ करणीय बिन्दु है जैसे मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु अध्ययन,स्वाध्याय,पढाई कार्य शुरू करने से पूर्व तीन बार १?का एवं एक मिनट मौन रखें । यह न्यास शिक्षा में भारतीयता को पुन: स्थापित करने और मानव चेतना के विकास भी जोर देता है। छात्रों में दयाभाव और सिंह जैसा साहस पैदा हो,छात्र संयमित बनें तथा प्रत्येक छात्र को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए।व्यक्ति नियमित जो भी कार्य करता है, वह उसकी आदत बन जाती है. लम्बे समय तक आदत रहने से वह उसका स्वाभाव बन जाता है वही चरित्र कहलाता है अच्छी आदतें ही मूल्य हैं हमारे शैक्षिक संस्थाओं एवं

परिवारों में अच्छी आदतों (मूल्य शिक्षा) के द्वारा व्यक्ति सदाचारी बनेगा, उनके आधार पर वह नैतिकता के रास्ते पर चलने हेतु सक्षम होगा जिससे समाज में चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होगा। कार्यक्रम का संचालन दीप नारायण पांडेय ने किया तथा योगाचार्य डॉ सत्येन्द्र सिंह ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का भी जोर देता है। छात्रों में दयाभाव और सिंह जैसा साहस पैदा हो,छात्र संयमित बनें तथा प्रत्येक छात्र को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए।व्यक्ति नियमित जो भी कार्य करता है, वह उसकी आदत बन जाती है. लम्बे समय तक आदत रहने से वह उसका स्वाभाव बन जाता है वही चरित्र कहलाता है अच्छी आदतें ही मूल्य हैं हमारे शैक्षिक संस्थाओं एवं

आतंकवाद पर वैश्विक मौन अस्वीकार्य

भारत के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है।

भारत का यह कदम एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ खासकर उन देशों के लिए एक चेतावनी है, जो आतंकवाद को अपने रणनीतिक हितों के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उसके व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होती है।

रूस तथा तीन मध्य एशियाई गणराज्यों द्वारा सीमा सुरक्षा विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संवाद था परंतु बीते वर्षों में यह मंच धीरे-धीरे चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे का उपकरण बनता गया है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इस संगठन की चुपगी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। इस बार के संयुक्त घोषणापत्र में ब्त्चिस्तान में कथित आतंकी घटनाओं का उल्लेख तो किया गया लेकिन पहलगाम जैसे जघन्य हमले को अनदेखा किया गया। भारत ने इसे पाकिस्तान के आरोपों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैधता देने की साजिश बताया। ब्त्चिस्तान में विद्रोही गतिविधियां वहां के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ी हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत-प्रायोजित आतंकवाद कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है। चीन, जो सीपीईसी के माध्यम से ब्त्चिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के इन दावों का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि भारत को इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार करना पड़ा। यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने एससीओ में ऐसा सख्त रुख अपनाया हो। बिश्केक (2019) और अस्ताना (2024) में भी भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि उस समय भारत ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु इस बार की परिस्थिति अलग थी। इस बार एक ऐसा हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई और उसे एससीओ की बैठक में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। भारत का यह कड़ा रुख केवल एससीओ तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। भारत का यह स्पष्ट संदेश था कि अब वह आतंकवाद के केंद्रों को उनकी सीमा में घुसकर खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह संदेश भी चीन और पाकिस्तान के लिए था कि भारत अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी आक्रामक कूटनीति अपना रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षामंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी स्पष्ट किया कि विश्वास-निर्माण तभी संभव है, जब चीन एलएस पर अतिक्रमण की

लोकतंत्र को मजबूत करने का रास्ता

भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति हमेशा सीमित रही है। 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में सिर्फ 74 महिलाएं चुनकर आईं, जो कुल सीटों का मात्र 13.6% हैं। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में भी घटा है और वैश्विक औसत 26.9% से काफी पीछे है। राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां औसतन केवल 9% ही महिलाएं विधायक हैं। यह न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाता है बल्कि नीति-निर्धारण की उस प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है जिसमें आधी आबादी की हिस्सेदारी नगण्य है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के निम्न स्तर के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है समाज की पितृसत्तात्मक सोच। महिलाओं को पारिवारिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे नेतृत्व के अवसर स्वाभाविक रूप से पुरुषों को मिलते हैं। 'सरपंच पति' जैसी प्रथाएं इस सोच को और भी स्पष्ट करती हैं।

से कमजोर प्रत्याशी होती हैं। लेकिन यह एक मिथक है, जिसे हाल के आंकड़े खारिज करते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाएं केवल 9.6% उम्मीदवार थीं, लेकिन उनकी सफलता दर पुरुषों से अधिक थी 5 उन्होंने 13.6% सीटें जीतीं। महिलाओं के सामने आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। देश में चुनाव लड़ना अत्यंत महंगा है और अधिकांश महिलाएं-खासकर ग्रामीण व पिछड़े वर्गों से-स्वतंत्र रूप से इतने संसाधन नहीं जुटा सकतीं। इसके अलावा, राजनीति का वातावरण भी महिलाओं के लिए असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण रहता है। उन्हें ट्रोलिंग, चरित्र हनन, और मानसिक उपीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे आत्मविश्वास डामगाता है। राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षित नेतृत्व विकास, और निर्णय लेने वाली इकाइयों में शामिल करने जैसी संस्थागत व्यवस्था भी अक्सर अनुपस्थित रहती है। महिला मोर्चा बनाकर उन्हें पार्टी के मुख्य दांचे से अलग कर दिया जाता है, जिससे वे सत्ता के निर्णायक केंद्रों से दूर रह

जाती हैं। 2029 के आरक्षण को सार्थक बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अब से ही तैयारी करनी होगी। सबसे पहला कदम है-स्वैच्छिक आंतरिक कोटा। रिकट वितरण में 33% महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना केवल आरक्षण की तैयारी नहीं, बल्कि समावेशी लोकतंत्र की दिशा में पहल होगी। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी जैसी मिसालें बताती हैं कि आंतरिक कोटा राजनीति की संस्कृति को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। दूसरा आवश्यक कदम है-वित्तीय सहायता और संरचित प्रशिक्षण। राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों के लिए अलग चुनावी फंड बनाना चाहिए ताकि वे चुनावी खर्च का बोझ उठा सकें। कनाडा का जूडी लामार्श फंड इसका अच्छा उदाहरण है। साथ ही, पंचायतों और नगरपालिकाओं में सक्रिय महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा और संसद स्तर के लिए तैयार करने का नेतृत्व कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। महिलाओं को पार्टी की कोर कमेटियों, नीति निर्माण इकाइयों और प्रवक्ता मंडल में भी सक्रिय भूमिका देनी चाहिए। केवल महिला मोर्चा या सांस्कृतिक

आयोजनों तक सीमित रखकर नेतृत्व नहीं उभरेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने हाल ही में कोर नेतृत्व में महिलाओं को शामिल किया है।अन्य दलों को भी यही दिशा लेनी चाहिए। मेटोरशिप भी एक सशक्त उपकरण हो सकता है। अनुभवी महिला नेता अगर नवोदित उम्मीदवारों को मार्गदर्शन दें, तो आत्मविश्वास, नीति की समझ, और रणनीतिक कौशल विकसित हो सकता है। इसके साथ ही, पार्टी के भीतर महिलाओं के खिलाफ उपीड़न या असम्मानजनक व्यवहार को रोकने के लिए सख्त आचार संहिता और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक दलों के प्रयासों के साथ-साथ मीडिया और नागरिक समाज की भी भूमिका अहम है। मीडिया को महिला नेताओं की नीतिगत भूमिका, वैचारिक दृष्टिकोण और सामाजिक योगदान पर केंद्रित करना चाहिए-ना कि उनके पहनावे, निजी जीवन या विवादों पर। नागरिक संगठनों को भी प्रशिक्षण, जनजागरण और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल लैंगिक समानता का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी मापदंड है। यदि प्रतिनिधित्व का आधार केवल पुरुषों की पहुँच और दबदबे तक सीमित रहेगा, तो लोकतंत्र का स्वरूप अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण केवल एक नीति नहीं, बल्कि नेतृत्व को समावेशी, संवेदनशील और संतुलित बनाने का औजार है। 2029 का चुनाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आएगा। अगर राजनीतिक दल अभी से महिला नेतृत्व को गढ़ने में निवेश नहीं करते तो यह आरक्षण भी केवल सत्ता में वंशवाद और प्रतीकात्मकता का विस्तार बनकर रह जाएगा। अब वक्त है कि दल ‘‘औरतों के लिए सीट छोड़ने’’ की बात नहीं करें, बल्कि ‘‘औरतों को नेतृत्व के लिए खड़ा करने’’ की पहल करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का यही असली रास्ता है।

क्या ये हेटस्पीच नहीं है

रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की गई। इमारात-ए-शरिया फुलवारी शरीफ की ओर से आयोजित इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू समेत सभी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इस रैली में इंडिया गठबंधन के दल शरीक हुए। जिसमें बिहार में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीं का हर एक-एक इंच, हर पन्ना चीख-चीखकर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। ये हम सब का देश है। वक्फ संशोधन कानून् लाकर किस तरह मस्जिदों, मदरसों, कब्रगाहों की जमीन को छीनने की योजना बनाई जा रही है, इसका खुलासा तेजस्वी ने किया और इसमें जमीन के बाद वोट छीनने की चालाकी के बारे में भी जनता को आगाह किया। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो फैसला लिया गया है, उसमें यह आशंका बढ़ रही है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कोट जाएंगे। अगर चुनाव आयोग यह कदम पहले उठाता, तब बात दूसरी होती, लेकिन चुनाव से चंद महीने पहले ही उसे मतदाताओं की जांच की जरूरत क्यों पड़ी, पिछले साल चुनाव से पहले इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। अवेध मतदाता, बागमदेशी घुसपैठिए इन शब्दों की आड़ में कहीं गरीबों, पिछड़ों के वोट का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अपने सहायक अपने गाता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र या अन्य पहचान वाले दस्तावेज जुटाना साधारण, गरीब आदमी के लिए आसान नहीं होगा। फिर चुनाव आयोग क्यों इस मुश्किल को खड़ा कर रहा है, यह विपक्ष की बड़ी आपत्ति है। जब गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के लिए लोग जुटे तो तेजस्वी यादव ने इस बारे में भी कहा कि आपको जमीन को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित सब लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर आपके वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आप लोग सचेत रहियेया और ऐसा होने मत दीजिएगा। भाजपा को उम्मीद नहीं होगी कि इस मंच का इस्तेमाल अब उसके बाकी फैसलों के विरोध के लिए भी हो सकता है। हालांकि अब तो भाजपा का जो नुकसान होना है, वो हो चुका है। अब इसकी भरपाई के लिए भाजपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस चक्कर में फिर एक गलती कर दी है। दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये इस बिल को प्रदेश में लाए नहीं होने देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बात को भाजपा संविधान और समाज का अपमान बता रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत लड़ा अघ्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की पत्वाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून (वक्फ बोर्ड कानून) दोनो सदनों से पारित है और कोर्ट में विचारार्थीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायापालिका का सम्मान।श्री त्रिवेदी यहीं नहीं रहेक, उन्होंने आगे कहा कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना, उसे तोड़ना है। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संंपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। कृषि प्रचामंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर ऐसे गंभीर विषयों पर चुप लग जाते हैं, या फिर दूर से बोलते हैं और अगर बोलते हैं तो उनमें ठोस तर्कों की जगह खोखली बातें ज्यादा होती हैं, इसलिए फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को ही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड कहा जाएगा। वक्फ संशोधन कानून का विरोध भाजपा की निगाह में संविधान, संसद, न्यायपालिका सबका अपमान है, तो फिर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का जो फैसला नरेन्द्र मोदी ने लिया था, क्या उसे भी भाजपा संसद का अपमान ही कहेगी, क्योंकि कृषि विधेयक भी संसद के दोनों सदनों से पारित होकर ही कानून बने थे।

हिन्दी को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाने

रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की गई। इमारात-ए-शरिया फुलवारी शरीफ की ओर से आयोजित इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू समेत सभी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इस रैली में इंडिया गठबंधन के दल शरीक हुए। जिसमें बिहार में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीं का हर एक-एक इंच, हर पन्ना चीख-चीखकर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। ये हम सब का देश है। वक्फ संशोधन कानून् लाकर किस तरह मस्जिदों, मदरसों, कब्रगाहों की जमीन को छीनने की योजना बनाई जा रही है, इसका खुलासा तेजस्वी ने किया और इसमें जमीन के बाद वोट छीनने की चालाकी के बारे में भी जनता को आगाह किया। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो फैसला लिया गया है, उसमें यह आशंका बढ़ रही है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कोट जाएंगे। अगर चुनाव आयोग यह कदम पहले उठाता, तब बात दूसरी होती, लेकिन चुनाव से चंद महीने पहले ही उसे मतदाताओं की जांच की जरूरत क्यों पड़ी, पिछले साल चुनाव से पहले इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। अवेध मतदाता, बागमदेशी घुसपैठिए इन शब्दों की आड़ में कहीं गरीबों, पिछड़ों के वोट का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अपने सहायक अपने गाता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र या अन्य पहचान वाले दस्तावेज जुटाना साधारण, गरीब आदमी के लिए आसान नहीं होगा। फिर चुनाव आयोग क्यों इस मुश्किल को खड़ा कर रहा है, यह विपक्ष की बड़ी आपत्ति है। जब गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के लिए लोग जुटे तो तेजस्वी यादव ने इस बारे में भी कहा कि आपको जमीन को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित सब लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर आपके वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आप लोग सचेत रहियेया और ऐसा होने मत दीजिएगा। भाजपा को उम्मीद नहीं होगी कि इस मंच का इस्तेमाल अब उसके बाकी फैसलों के विरोध के लिए भी हो सकता है। हालांकि अब तो भाजपा का जो नुकसान होना है, वो हो चुका है। अब इसकी भरपाई के लिए भाजपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस चक्कर में फिर एक गलती कर दी है। दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये ये इस बिल को प्रदेश में लाए नहीं होने देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बात को भाजपा संविधान और समाज का अपमान बता रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत लड़ा अघ्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की पत्वाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून (वक्फ बोर्ड कानून) दोनो सदनों से पारित है और कोर्ट में विचारार्थीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायापालिका का सम्मान।श्री त्रिवेदी यहीं नहीं रहेक, उन्होंने आगे कहा कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना, उसे तोड़ना है। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संंपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। कृषि प्रचामंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर ऐसे गंभीर विषयों पर चुप लग जाते हैं, या फिर दूर से बोलते हैं और अगर बोलते हैं तो उनमें ठोस तर्कों की जगह खोखली बातें ज्यादा होती हैं, इसलिए फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को ही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड कहा जाएगा। वक्फ संशोधन कानून का विरोध भाजपा की निगाह में संविधान, संसद, न्यायपालिका सबका अपमान है, तो फिर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का जो फैसला नरेन्द्र मोदी ने लिया था, क्या उसे भी भाजपा संसद का अपमान ही कहेगी, क्योंकि कृषि विधेयक भी संसद के दोनों सदनों से पारित होकर ही कानून बने थे।

हिन्दी को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाने

रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की गई। इमारात-ए-शरिया फुलवारी शरीफ की ओर से आयोजित इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू समेत सभी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इस रैली में इंडिया गठबंधन के दल शरीक हुए। जिसमें बिहार में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीं का हर एक-एक इंच, हर पन्ना चीख-चीखकर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। ये हम सब का देश है। वक्फ संशोधन कानून् लाकर किस तरह मस्जिदों, मदरसों, कब्रगाहों की जमीन को छीनने की योजना बनाई जा रही है, इसका खुलासा तेजस्वी ने किया और इसमें जमीन के बाद वोट छीनने की चालाकी के बारे में भी जनता को आगाह किया। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो फैसला लिया गया है, उसमें यह आशंका बढ़ रही है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कोट जाएंगे। अगर चुनाव आयोग यह कदम पहले उठाता, तब बात दूसरी होती, लेकिन चुनाव से चंद महीने पहले ही उसे मतदाताओं की जांच की जरूरत क्यों पड़ी, पिछले साल चुनाव से पहले इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। अवेध मतदाता, बागमदेशी घुसपैठिए इन शब्दों की आड़ में कहीं गरीबों, पिछड़ों के वोट का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अपने सहायक अपने गाता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र या अन्य पहचान वाले दस्तावेज जुटाना साधारण, गरीब आदमी के लिए आसान नहीं होगा। फिर चुनाव आयोग क्यों इस मुश्किल को खड़ा कर रहा है, यह विपक्ष की बड़ी आपत्ति है। जब गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के लिए लोग जुटे तो तेजस्वी यादव ने इस बारे में भी कहा कि आपको जमीन को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित सब लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर आपके वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आप लोग सचेत रहियेया और ऐसा होने मत दीजिएगा। भाजपा को उम्मीद नहीं होगी कि इस मंच का इस्तेमाल अब उसके बाकी फैसलों के विरोध के लिए भी हो सकता है। हालांकि अब तो भाजपा का जो नुकसान होना है, वो हो चुका है। अब इसकी भरपाई के लिए भाजपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस चक्कर में फिर एक गलती कर दी है। दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये ये इस बिल को प्रदेश में लाए नहीं होने देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बात को भाजपा संविधान और समाज का अपमान बता रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत लड़ा अघ्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की पत्वाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून (वक्फ बोर्ड कानून) दोनो सदनों से पारित है और कोर्ट में विचारार्थीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायापालिका का सम्मान।श्री त्रिवेदी यहीं नहीं रहेक, उन्होंने आगे कहा कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना, उसे तोड़ना है। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संंपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। कृषि प्रचामंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर ऐसे गंभीर विषयों पर चुप लग जाते हैं, या फिर दूर से बोलते हैं और अगर बोलते हैं तो उनमें ठोस तर्कों की जगह खोखली बातें ज्यादा होती हैं, इसलिए फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को ही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड कहा जाएगा। वक्फ संशोधन कानून का विरोध भाजपा की निगाह में संविधान, संसद, न्यायपालिका सबका अपमान है, तो फिर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का जो फैसला नरेन्द्र मोदी ने लिया था, क्या उसे भी भाजपा संसद का अपमान ही कहेगी, क्योंकि कृषि विधेयक भी संसद के दोनों सदनों से पारित होकर ही कानून बने थे।

भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है।

अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे है, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी মানুষ की शक्ति से हार गई, पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारे सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है। भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है। फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक तात्कवर

राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मांससून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोधी की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरुआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से भाजपा के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती गई। ऐसे में निश्चित ही मराठा राजनीति से हिन्दी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अब तक तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जाना जाता था, पर इधर तोखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली हिन्दी भाषा अपने ही देश में उपेक्षा एवं राजनीति की शिकार है। अब केन्द्र सरकार के साथ-साथ हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। हिन्दी भाषी प्रांतों को अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे

सबक लेंगे? हालांकि, जिस तरह की त्रासद भाषा-राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि इसके लिये बनी समितियों में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएग और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हासिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में बढ़ते हिन्दीभाषियों के अनुपात को देखते हुए देर-सबेर हिन्दी को अपनाना ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र, कुल आबादी में हिंदीभाषियों का बढ़ता अनुपात हिन्दी के पक्ष में है। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिंदीभाषियों की संख्या मुंबई में 25.9 प्रतिशत और मराठीभाषियों की 42.9 प्रतिशत थी जो 2011 में क्रमशः 30.2 प्रतिशत और 41 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में इसी अवधि में जहां मराठीभाषी आबादी 76 प्रतिशत से 73.4 प्रतिशत पर आ गई, वहीं हिंदीभाषियों का अनुपात 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। इसीलिये हिंदी लादने के इस फैसले ने न केवल उद्धव और राज ठाकरे को आक्रामक रूप में सामने ले आई बल्कि 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। 5 जुलाई को होने वाली हिन्दी विजय रैली पर महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर सुरू में सुरू मिलाने वाले उद्धव और राज ठाकरे को सियासी होसला मिल गया है। जिसे महाराष्ट्र की

सियासत में एक नया मोड़ माना जा रहा, लेकिन साथ ही सवाल है कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री कब तक बरकरार रहेगी। हिंदी बनाम मराठी विवाद को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ स्थानीय दलों ने हिंदी भाषी प्रवासियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेकर हिंदी भाषा पर परोक्ष रूप से प्रहार किया है। इससे न केवल भाषा के नाम पर लोगों में दूरी बढ़ी है, बल्कि महाराष्ट्र की समावेशी छवि को भी आघात पहुंचा है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पुणे, और नासिक में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी समुदाय निवास करता है। ये लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब इनकी भाषा को दोषम दर्जे का माना जाता है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा 'एकता में अनेकता' के विपरीत है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी और मराठी दोनों को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की राजभाषा है और मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा। किसी भी राज्य में भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर दूसरी भाषाओं को अपमानित करना न तो संवैधानिक है और न ही नैतिक। भाषायी सह-अस्तित्व के लिये महाराष्ट्र में मराठी को सर्वोच्च स्थान मिले, लेकिन हिंदी भाषा को भी सम्मान मिले, यह संतुलन ही स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। स्कूलों में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी- तीनों भाषाओं को समुचित महत्व देकर बच्चों में बहुभाषिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दल भाषाय एवं केन्द्र सरकार को घेरने के लिये जिस तरह भाषा, धर्म एवं जातियता को लेकर आक्रामक रवैया अपनाते हुए देश में अशांति, अराजकता एवं नगरत को फैला रहे रहें हैं, यह चिन्ताजनक है। महाराष्ट्र में हिन्दी का विरोध अंधश्रद्धाकारी है। आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बावजूद हिन्दी को उसका उचित स्थान न मिलना विडम्बना एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

स्काउट-गाइड बनेंगे स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्ति अभियान के संवेसडर

- डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद की बैठक, 11 प्रस्तावों पर चर्चा, आगामी कार्यक्रमों को मिली मंजूरी
- डीएम ने दिए निर्देश, स्कूली छात्र निभाएंगे ‘‘पर्यावरण प्रहरी’’ की भूमिका

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। प्रादेशिक मुख्य आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार के निर्देशन में भारत स्काउट एंड गाइड की जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम एवं परिषद की अध्यक्ष दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। बैठक की

द्वेष भावना से वैमनस्यता फैलाने वालों की निंदा की



राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोला गोकर्णनाथ खीरी। कुर्मी क्षत्रिय समाज कल्याण समिति की एक आपात बैठक का आयोजन मंगलवार की शाम गोला की मिल बाईपास रोड स्थित पटेल संस्थान में अध्यक्ष संजेल वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। जिसका संचालन आशिकर वर्मा ने किया है। बैठक में द्वेष और संकुचित भावना से प्रसित कुछ चंद लोगों के द्वारा वैमनस्यता फैलाने का कृत्य किया जा रहा है। ऐसे लोग आपसी भाईचारा,

छोटे भाई ने घर पर किया कब्जा, पीड़ित ने दी अनशन की चेतावनी

बाँदा। अतरंग थाना क्षेत्र स्थित नगर में नहर पर बिसंछा रोड निवासी सन्तराम पुत्र फकीरा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर अपने छोटे भाई पर घर का ताला तोड़कर मकान पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है पीाड़ित सन्तराम ने पत्र में बताया,कि वह जब जीविकोपार्जन के सिलसिले में बाहर गया था,तभी उसके छोटे भाई श्यामलाल पुत्र फकीरा ने अपनी पत्नी और बेटों के साथ मिलकर मकान का ताला तोड़ दिया और जबरन कब्जा कर लिया।लौटने पर जब सन्तराम ने पुनः अपने घर में रहने की बात कही तो उसे गालियाँ दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई।सन्तराम ने चेतावनी दी है,कि यदि उसे शोही ही उसका घर नहीं दिलाया गया तो वह मुख्यालय स्थित अशोक लाट में क्रमिक अनशन शुरू करने के लिए मजबूर होगा।इस संबंध में वह जिलाधिकारी को भी पत्र सौंप चुका है।पीाड़ित ने श्यामलाल व उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

आचार्य द्विवेदी स्मृति पार्क एवं प्रतिमा स्थल का भूमिपूजन संपन्न

- अमेठी के सांसद केएल शर्मा, पद्मश्री सुधा सिंह एवं नगर पालिकाध्यक्ष ने की विधिविधान से पूजा
- 15.30 लाख रुपए से निर्मित होगा पार्क, रिलीज हुई डिजाइन
- आचार्य द्विवेदी समिति जनसहयोग से स्थापित करेगी 10 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

रायबरेली। अमेठी के सांसद केएल शर्मा, पद्मश्री सुधा सिंह एवं नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने सई नदी के किनारे राजघाट पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति पार्क एवं प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। पंडित चंद्रभाल शास्त्री ने विधि विधान



से पूजन अर्चन संपन्न कराया। 2 महीने में निर्माण पूरा होने के बाद समिति को सौंप दिया जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति पार्क में 10 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा

लखीमपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अयोध्या, बरेली

लखीमपुर खीरी। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रद्धा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के दिशा निर्देशन में काउंसलरों के सहयोग से 11 परिवारिक विवादों में सुलह का प्रयास करके 05 जोड़े पति-पत्नी की विवाद कराके टूटने के कगार पर पहुंचें रिश्तों को पुनः जोड़ने का सराहनीय कार्य किया गया है।



आयव्यय प्रस्तुतिकरण, वर्ष 2025-26 के प्रशिक्षण व कार्यक्रमों के अनुमोदन समेत कुल 11 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा और अनुमोदन किया गया। जिला कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक का संचालन जिला सचिव डॉ के.सी मिश्रा एवं पर्यवेक्षण सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त लखनऊ मंडल पूनम संधू ने किया। पूनम संधू ने बैठक की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई।

पयावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने में स्काउट गाइड की भूमिका निर्णायक होगी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि स्काउट-गाइड के छात्र अनुशासन, सेवा और नेतृत्व के प्रतीक हैं। उनकी भागीदारी से समाज में जनजागरूकता के अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकते हैं।

बैठक में वर्ष 2024-25 के आय-व्यय अनुमोदन, वार्षिक

पलिया नगर की पहली बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, मोहल्ले बने जलमग्न टापू

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। पलिया नगर में सोमवार देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की तैयारियों की पूरी पोल खोलकर रख दी है। नगर के प्रमुख मोहल्ले – इकतम नगर, महिगिरान, रंगरेजान समेत अनेक क्षेत्रों में जलभराव और नालियों के ओवरफ्लो होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों से लेकर गलियों और लोगों के घरों-दुकानों तक नालियों का गंदा पानी भर गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासी आसिफ हुसैन, रहमान, मोहम्मद अली और कई दुकानदारों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही नगर के कई हिस्सों में पानी भर गया। उन्होंने नगर पालिका के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नगर



वासियों का कहना है कि नई सड़कों का

महिला थाना से काउंसलिंग के द्वारा हुई 05 जोड़े पति-पत्नी की हुई विदाई

लखीमपुर खीरी। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रद्धा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के दिशा निर्देशन में काउंसलरों के सहयोग से 11 परिवारिक विवादों में सुलह का प्रयास करके 05 जोड़े पति-पत्नी की विवाद कराके टूटने के कगार पर पहुंचें रिश्तों को पुनः जोड़ने का सराहनीय कार्य किया गया है।

लखीमपुर खीरी। जनपद के मोहम्मदी कस्बे में विगत रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। मोहम्मदी कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक (एसआई) रमेश शुक्ला को देर रात सीओ ऑफिस के समीप एक आवारा सांड ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस समय हुई जब वे ड्यूटी से लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्हें गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई।

एसआई रमेश शुक्ला अपने सौम्य स्वभाव, कार्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत से पुलिस विभाग और मोहम्मदी क्षेत्र में, शोक की लहर दौड़ गई है। उनके परिवजनों को गहरा आघात पहुंचा है, वहीं सहयोगी पुलिसकर्मी भी बेहद मर्माहत हैं। यह हादसा एक बार फिर इस बात की

आवारा सांड की टक्कर से घायल एसआई रमेश शुक्ला का निधन

- आवारा पशुओं की समस्या बनी जानलेवा

लखीमपुर खीरी। जनपद के मोहम्मदी कस्बे में विगत रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। मोहम्मदी कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक (एसआई) रमेश शुक्ला को देर रात सीओ ऑफिस के समीप एक आवारा सांड ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस समय हुई जब वे ड्यूटी से लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्हें गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई।

एसआई रमेश शुक्ला अपने सौम्य स्वभाव, कार्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत से पुलिस विभाग और मोहम्मदी क्षेत्र में, शोक की लहर दौड़ गई है। उनके परिवजनों को गहरा आघात पहुंचा है, वहीं सहयोगी पुलिसकर्मी भी बेहद मर्माहत हैं। यह हादसा एक बार फिर इस बात की



ओर इशारा करता है कि नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या किस कदर विकराल रूप ले चुकी है। मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों तक सांड, गाय-बैल खुलेआम घूमते रहते हैं।

कई बार ये पशु लोगों पर हमला कर चुके हैं, वाहन चालकों के लिए भी ये बड़ा खतरा बन चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर प्रशासन और संबंधित विभागों को इस दिशा में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन

सैकड़ों दिव्यांगों का गोला इंदिरा गांधी पार्क में धरना जारी, अधिकारों की अनदेखी पर जताया आक्रोश

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

गोला गोकर्णनाथ खीरी। गोला छोटी काशी कहे जाने वाले क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी पार्क में सैकड़ों दिव्यांगजन पिछले दो दिनों से लगातार बारिश और भीषण गर्मी के बीच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। भारतीय दिव्यांग यूनियन के बैनर तले यह प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें गोला तहसील अध्यक्ष विकास कुमार, रियाजुद्दीन सभासद, हरीश कुमार और शाहित जैसे प्रमुख लोग शामिल हैं। प्रदर्शनकारी दिव्यांगजनों का कहना है कि उन्होंने 18 जून 2025 को जिलाधिकारी महोदय को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप था, लेकिन अब तक न तो कोई प्रतिक्रिया मिली है और न ही कोई अधिकारी या कर्मचारी उनसे मिलने आया है। मुख्य मांगों- अत्योद्य रशन कार्ड में दिव्यांगों को प्राथमिकता। मुद्रा लोन योजनाओं में दिव्यांगों को वरीयता। रोडवेज बसों में सम्मानजनक यात्रा की

सुविधा। सरकारी अस्पतालों में अलग काउंटर व प्राथमिकता। मंडी समितियों में दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ। भूमिहीन दिव्यांगों को ग्राम समाज व परती भूमि का आवासीय पट्टा। प्रदर्शनकारी दिव्यांगों का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपनी ट्राईसाइकलों और मोटरसाइज्ड वाहनों से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च कर धरना देंगे। समर्थन में आए नेता- इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा और भाकियू जिला अध्यक्ष कुलवंत सिंह का समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन की अनदेखी करना जिला प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है और यदि मांगे नहीं मानी गई, तो इसके परिणामों की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

आरआरबी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। ललित सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AIGBOO ``भारतीय मजदूर संघ,, ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों टटउप में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की दीर्घकालिक उपेक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह वक्तव्य देश की जनता और संबंधित प्रशासनिक तंत्र का ध्यान आरआरबी कर्मियों की अनदेखी हो रही न्यायसंगत मांगों की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। ललित सिंह ने बताया कि लगातार संवादहीनता और समस्याओं के समाधान में विलंब के चलते, अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन (AIGBOO) एवं अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक वर्कर्स संगठन (AIGBWO) – जो भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध हैं –



ने चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति अपनाई है। इसका उद्देश्य RRB कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को सार्वजनिक रूप से सामने लाना और समाधान की दिशा में दबाव बनाना है। प्रमुख मांगें आरआरबी के प्रस्तावित आईपीओ को रद्द किया जाए, जिससे इनकी सार्वजनिक एवं ग्रामीण प्रकृति सुरक्षित रह सके। .स्थानांतरण नीति में

व्याप्त असमानताओं को समाप्त किया जाए। सेवा शर्तों में पूर्ण समानता लागू हो जैसे अवकाश नीति, स्ट्याफ ऋण, आवास भत्ता, आदि। 12वें द्विपक्षीय और 9वां संयुक्त नोट बिना विचलन के लागू किया जाए। पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित हो और पदेनन्ति की नीति व्यापकजैिक बैंकों के अनुरूप हो। दीर्घकाल से सेवा दे रहे अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवा लाभों का खर्च बैंक प्रबंधन द्वारा वहन किया जाए। RRB ट्रेड यूनियनों को IBA की वार्ताओं में सम्मिलित किया जाए, और उनके पदाधिकारियों को विशेष अवकाश मिले। पांच दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस और पुरानी पेंशन योजना की मांग तत्काल पूरी की जाए। 1 व 2 जुलाई 2025 5 कर्मचारियों द्वारा करी पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन।

27 वर्षों से चल रहा है स्मृति संरक्षण अभियान

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति पिछले 27 वर्षों से आचार्य जी की स्मृतियों को संरक्षित करने का अभियान चला रही है। इसी क्रम में नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित पार्क भी है। समिति की ओर से हर साल आचार्य जी की याद में राष्ट्रीय व्यक्तित्व को युग प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सुमित के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि पार्क में स्थापित होने वाली मूर्ति का आँर्डर दे दिया गया है। पार्क का निर्माण पूरा होते ही मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी।

भूमि पूजन में यह गणमान्य लोग रहे उपस्थित

भूमि पूजन समारोह में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ मनीष चौहान, डॉ बृजेश सिंह, सचिव डॉ संजीव जायसवाल, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष युगल किशोरी तिवारी, गिरीश मिश्रा, कृष्णानंद मिश्रा, कमलेश द्विवेदी, दादा जेपी त्रिपाठी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीके शुक्ल, उपाध्यक्ष विजय शंकर अग्निहोत्री प्रमोद पाल सिंह गुलाटी, महासचिव अजीत सिंह, लाल आशाकिरण सिंह राहुल वाजपेई, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास त्रिपाठी, व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता, गुरुजीत तनेजा, मुकेश रस्तोगी, साहित्यकार दुर्गा शंकर वर्मा, सूर्य प्रसाद शर्मा, इटा के संस्थापक संतोष डे, संतोष चौधरी, श्रीमती किर्ण शुक्ला, श्रीमती रेनु श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत शुक्ला, समाजसेवी लल्लन मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र अग्रवाल, सभासद परमजीत सिंह गांधी, धर्मेन्द्र द्विवेदी, वीरेंद्र शक्व, पूर्व सभासद पूनम तिवारी समित के कोषाध्यक्ष विनय द्विवेदी, सदस्य अरुण सिंह, महेश प्रताप सिंह, वीरेंद्र विक्रम सिंह, राजीव भार्गव, स्वतंत्र पांडेय, करुणा शंकर मिश्रा, राजेश द्विवेदी, राजेश वर्मा, अभिषेक मिश्रा, शशिकांत अवस्थी, क्षमता मिश्रा, प्रिया पांडेय के साथ नगर के तमाम गणमान्य नागरिक शामिल रहे।

हम लोगों का फर्ज है कि जनपद के महापुरुषों की स्मृतियों को आगे बढ़ाना। पद्मश्री सुधा सिंह ने कहा कि महापुरुषों की यादों से संजोया जाना जरूरी है। इसमें हर संभव सहयोग किया जाएगा। नगर पालिकाध्यक्ष शत्रोहन सोनकर ने बताया कि पार्क की लागत लगभग 15

लाख 30 हजार रुपये है। उन्होंने पार्क की डिजाइन रिलीज करते हुए कहा कि गुरुवार से पार्क का निर्माण शुरू कर हो जाएगा। यह स्मृति पार्क आचार्य द्विवेदी के साहित्यिक अवदान को जनमानस में जीवंत बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। पूजा में

समाजसेवी सुशील कुमार गुप्ता, राही के ब्लॉक प्रमुख धर्मेन्द्र यादव, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी, महामंत्री योगेंद्र दीक्षित, भाजपा के नगर अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी शामिल रहे।



भूमि पूजन अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने किया।

उन्होंने कहा कि आचार्य द्विवेदी समिति अपने संयोजक गौरव अवस्थी के नेतृत्व में पिछले 27 वर्षों से युग पुरुष

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृतियों को सुरक्षित करने का अनुकरणीय काम कर रही है। समिति ने आचार्य जी की स्मृतियों से जुड़ने का अवसर भूमि पूजन के बहाने दिया है।

खेल/बिजनेस

**पंत आईसीसी रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंचे
बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार**

विंबलडन 2025: फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गॉफ पहले ही दौर में बाहर

संक्षिप्त समाचार

वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, सैमी ने न्याय और सही प्रक्रिया की मांग की

सेंट जॉर्ज (ग्रेनाडा)। वेस्टइंडीज की वर्तमान टीम के एक सदस्य पर यौन उत्पीड़न के भीमर आरोप लगाए गए हैं जिसके बाद टीम के मुख्य कोच डेरेन सैमी ने न्याय की मांग की है, लेकिन साथ ही उचित प्रक्रिया का पालन करने पर भी जोर दिया है। ग्याना के कैप्टन न्यूमैन में पिछले सप्ताह प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक किशोरी सहित 11 महिलाओं ने इस अज्ञात क्रिकेटर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिनमें से कुछ कथित तौर पर 2023 तक के हैं। अभी तक कोई औपचारिक मामला दायर नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए सैमी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया तथा कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करने पर जोर दिया। पूर्व कप्तान सैमी ने कहा, 'मीडिया में जो कुछ चल रहा है, उससे हम सभी वाकिफ हैं। मैं अपने खिलाड़ियों के बहुत करीब हूँ। मैंने उनसे बातचीत की है। एक बात मैं कह सकता हूँ कि हम न्याय में विश्वास करते हैं। हमारा समुदाय ऐसा है जो मानता है कि न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हालांकि, इसकी एक प्रक्रिया है। आरोप लगाए गए हैं और हम अपनी तरफ से हरसंभव मदद करेंगे, ताकि उचित प्रक्रिया और सही प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सैमी ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ये आरोप हैं। हम न्याय प्रणाली को जानते हैं। आपको प्रक्रिया के लिए इंतजार करना होगा। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। जो जानकारी सामने आई है, वही हमारे पास है। मूझे पूरा यकीन है कि अंत में न्याय होगा। जब सैमी से पूछा गया कि क्या क्रिकेट वेस्टइंडीज ने जांच शुरू की है तो उन्होंने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'इमानदारी से कहूँ तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मूझे पूरा यकीन है कि वे सही प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार से यहां खेला जाएगा।

ऐमा नवारो के खिलाफ हार के साथ विक्टोवा ने विबलडन को अलविदा कहा

लंदन। दो बार की चैंपियन पेन्ना विक्टोवा ने मंगलवार को यहां अमेरिका की ऐमा नवारो के खिलाफ हार के साथ अपने परकीदा ग्रैंडस्लेम टूर्नामेंट विबलडन को अलविदा कहा। चक गणराज्य की 35 साल की विक्टोवा को 10वीं वरीय नवारो के खिलाफ सील्स सेट में 3-6, 1-6 से हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2011 और 2014 में यहां खिताब जीतने वाली विक्टोवा ने सितंबर में होने वाले अमेरिकी ओपन के बाद डबल्यूटीए ओपन को अलविदा कहने की योजना बनाई है। शायद विक्टोवा ने मेच के बाद कोर्ट पर दिए साक्षात्कार में कहा, “यह जगह मेरे लिए सबसे अच्छी यादें समेटे हुए है। उन्होंने कहा, “मैंने कभी विबलडन जीतने का सपना नहीं देखा था और मैंने इसे दो बार जीता। यह बेहद खास बात है। विक्टोवा ने कहा, “मुझे विबलडन की कमी खलेगी। यूएस टेनिस की कमी खलेगी, मुझे आप प्रशंसकों की कमी खलेगी लेकिन मैं जीवन के अगले अध्याय के लिए भी तैयार हूं। वाइल्ड कार्ड आमंत्रण पर यहां खेलने वाली विक्टोवा मातृत्व अवकाश के कारण पिछले साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाई थी। विक्टोवा ने 2011 में यहां फाइनल में मारिया शारापोवा को 6-3, 6-4 जबकि 2014 में फाइनल में युगिनी बुचाई को 6-3, 6-0 से हराया था।

गुइरासी के दो गोल से डॉर्टमंड क्वार्टर फाइनल में

गोंजालो गार्सिया के गोल से रियाल मैड्रिड
क्लब विश्व कप क्वार्टर फाइनल में

मियामी गार्डन (अमेरिका)। गोंजालो गार्सिया ने क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपना तीसरा गोल किया, जिससे रियाल मैड्रिड ने राउंड ऑफ 16 में युवेंटस को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्टार स्ट्राइकर क्लियन एम्बाप्पे की गैस्ट्रोटेटेस्टाइन बीमारी के कारण गार्सिया ने रियाल मैड्रिड के सभी चार मैचों में शुरुआत की है। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने मंगलवार को 54वें मिनट में हेडर से गोल किया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। गार्सिया को 68वें मिनट में बाहर भेज दिया गया, जबकि एम्बाप्पे ने क्लब विश्व कप में पदार्पण किया। बीमारी के कारण वह कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहे और युष्प चरण के तीनों मैच में नहीं खेल पाए थे।

मेडी अस्सिस्ट ने पैरामाउंट टीपीए का अधिग्रहण पूरा किया

नयी दिल्ली। मेडी अस्सिस्ट इश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड ने पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इश्योरेंस टीपीए में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। मेडी अस्सिस्ट टीपीए ने बुधवार को बयान में कहा कि औपचारिक विलय प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेंगी। इससे एक सहज बदलाव सुनिश्चित होता है क्योंकि दोनों कंपनियां अपने परिचालन को एकूँकृत करती हैं और बेहतर मूल्य सृजन के लिए अपनी पेशकशों को संरक्षित करती हैं। बयान के अनुसार, इस लेन-देन के साथ मेडी अस्सिस्ट को स्वास्थ्य प्रीमियम में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। यह सौदा इसके प्रदाता नेटवर्क को भी बढ़ाता है और इस सभी स्वास्थ्य बीमा खातों में सेवाओं को अधिक कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए परिचालन तालमेल का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

डोप टेस्ट से बचने के लिए
चार एथलीटों पर लगा
प्रतिबंध कम किया गया

नयी दिल्ली। ट्रैक एवं फील्ड एथलीटों को प्रेरणा देने के लिए, पंजाब और चेन्नई में आयोजित प्रत्यक्ष प्रारंभिक परीक्षाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण गया चार साल का प्रतिबंध एक-दो साल के लिए कम कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपराध लगाने के 20 दिन के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

चारों खिलाड़ी उन कई एथलीटों में शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष की शुरूआत में राष्ट्रीय खेल दिवस (गोष्ठी) में भाग लेना नहीं मिला था, जो राष्ट्रीय खेल दिवस (गोष्ठी) में भाग लेने वाले थे।

नियमों के अनुसार उन्हें 2.3 के तहत निर्धारित सीमा के बिना किसी ठोस कारण के नमूना संग्रहण के लिए प्रेषण होने से बचने, काम करने या असफल होने से संबंधित है। पहली बार अपराध करके प्रारंभिक प्रतियोगिताएं अनुच्छेद 10.8.1 के तहत अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो उनका सजा कम की जा सकती है। इसलिए अनुच्छेद के अनुसार, चार वर्ष के प्रतिबंध से दंडित खिलाड़ियों को एक वर्ष की छुट्टी मिलेगी, बजाय वे अपना अपराध और अपराध लगाने के 20 दिनों के भीतर दंड स्वीकार कर लें।

एशियाई चैंपियन 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी

नयी दिल्ली। एशियाई चैंपियन राष्ट्रों का रिकार्डों का एक धारक 100 मीटर बाधा दौड़ धाविका ज्योति यादवी को 'कुछ दिन पहले' ट्रेनिंग के दौरान घुटने में चोट लग गई जिससे सितंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली यादवी के पास सितंबर में तोयोको में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने का अच्छा मौका है लेकिन हाल में लगी चोट उनकी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। राष्ट्रिय रिकार्डों (12.78 सेकेंड) धारक यादवी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान मेरे घुटने में दुर्भाग्यपूर्ण चोट लगने के कारण मुझे ब्रेक लेना पड़ा। पिछले साल पेरिस ओलंपिक के बाद चोटिल होने के 25 मंजूसला सत्र में वापसी करने वाली 25 वर्षीय यादवी ने कहा, "मैं अपने कविल्लों का आकलन करने और भविष्य पर निर्णय लेने के लिए अप्रैल में मेडिकल टीम के साथ काम कर रही

100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी

A female athlete, likely a sprinter, is captured in a dynamic pose during a race. She is wearing a dark blue singlet with red trim and the number 102, along with dark blue shorts. Her expression is one of intense focus and effort. The background shows a blurred track and stadium seating, emphasizing the speed of the action.

याराजी चोटिल जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए केशव महाराज मल्डर होंगे

बवालीफाईंग स्तर को हासिल करके
सीमा प्रवेश और दूसरा, विश्व रैंकिंग
कोटा के माध्यम से। बवालीफिकेशन
की समय-सीमा 24 अगस्त तक है।
याराजी को 2024 पेरिस ओलिंपिक के
बाद फिनलड में प्रशिक्षण के दौरान
कुदृष्ट में चोट लगी थी जिसके कारण
उनकी ट्रेनिंग पर असर पड़ा। मौजूदा
सत्र की शुरुआत में याराजी ने अपनी
तकनीक में बदलाव किया। उन्होंने
कहा, “चोटें एथलीट के सफर का
हिस्सा होती हैं और मैं इसे एक और
बाधा के रूप में देख रही हूँ जिस मैं
आप सभी के समर्थन और आशीर्वाद
से जल्द ही पार कर लूंगी। मैं और
अधिक मजबूत होकर वापस आऊंगी।
याराजी ने फरवरी में उत्तराखंड राष्ट्रीय
खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ और
200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप खिताब
का बचाव करने से पहले फ्रेडरेडेशन
कप में 100 मीटर बाधा दौड़ में शीर्ष
स्थान हासिल किया। उनका पिछला
खिताब सात जून को ताइवान
एथलेटिक्स सोप में आया।

सरकार ने कैब कंपनियों को 'व्यस्ततम समय' के दौरान आधार मूल्य का दोगुना तक शुल्क लेने की अनुमति दी

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन
मंत्रालय ने कैब एग्रीटरर्स (सेवा
प्रदाताओं) को 'पीक ऑव'
(व्यस्तमय समय) के दौरान आधार
मूल्य का दो गुना तक शुल्क लगाने में
अनुमति दे दी है, जो पहले 1.5 गुना
था। गैर व्यस्तमय समय के लिए
क्रिया, आधार मूल्य का न्यूनतम 50
प्रतिशत होना चाहिए। सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने 'मोटर
वाहन एग्रीटरटर दिशानिर्देश-2025' में
कहा है कि 'एग्रीटरटर को मूल क्रियायें से
न्यूनतम 50 प्रतिशत कम क्रियायें लेने
की तथा उप-खण्ड (17.1) के तहत
निर्दिष्ट आधार क्रियायें से अधिकतम दो
गुना गतिशील मूल्य निर्धारण की
अनुमति होगी। इसके अलावा, भ्रम्य
आधार क्रियायें न्यूनतम तीन किलोमीटर
के लिए होगा, ताकि 'डैट माइलेज' को
भरपाई की जा सके। इसमें बिना यात्री

के यात्रा की गई दूरी, यात्रा की गई दूरी और यात्री (यात्रियों) को लेने के लिए उपयोग किया गया ईंधन शामिल है। विश्वानिर्देशों के अनुसार, मोटर वाहनों संबंधित श्रेणी या वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिष्पृचित किया, एग्जीग्रेट से सेवानें प्राप्त करने वाले यात्रियों के लिए दीन आकर किया जाता है। राज्यों को तीन महीने के भीतर संशोधित विश्व-निर्देशों को अपनाने की सामल दी गई है। केबल रद्दीकरण, मोटर वाहन में, अगर रद्दीकरण, एग्जीग्रेट द्वारा वैध कारण के बिना किया जाता है तो चालक पर कियारे का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा, जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। बिना किसी वैध कारण के टिकट रह करने पर यात्री पर भी इसी प्रकार का जुर्माना लगाया जाएगा। विश्व-निर्देशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार एग्जीग्रेट के रूप में लाइसेंस से के लिए आवेदन की एकल-खिड़की मंजूरी के लिए एक पोर्टल

विकसित और नामित करेगा। इसमें कहा गया है, एग्रीगेटर द्वारा देय लाइसेंस शुल्क पांच लाख रुपये होगा और लाइसेंस जारी होने को तय होने से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा। एग्रीगेटर्स को यह सुनिश्चित करना आवश्यक किया गया है कि ड्राइवों (वहन चालकों) के पास कम से कम क्रमशः पांच लाख रुपये और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य और सावधि बीमा हो। दिशा-निर्देशों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि एग्रीगेटर द्वारा एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, एग्रीगेटर को ऐसे वाहनों को शामिल नहीं करना चाहिए जो प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा शामिल किए गए सभी वाहनों को प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

क्रिजैक लिमिटेड का आईपीओ खुला

निवेशक 4 जुलाई तक कर सकेंगे निवेश

नई दिल्ली। क्रिजैक लिमिटेड का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आरंभिक सार्वजनिक निगम (ओएफएस) होगा, जिसके तहत कुल

आईपीओ) निवेशकों के लिए बुधवार को खुल गया। निवेशक इस इश्यू के लिए 4 जुलाई तक बोली लगा सकेगे। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 233-245 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसके शेयर 9 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर लिस्ट होंगे। विदेशी शिक्षा क्षेत्र का प्रमुख कंपनी क्रिजैक लिमिटेड इस आईपीओ के लिए 860 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। कंपनी ने अपने पहले निगम के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए मूल्य का दायरा 233-245 रुपये तय किया गया है। निवेशक इसके लिए न्यूनतम 61 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 61 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं, उसके बाद इस मूल्य के लिए 61-61 के मल्टीपल में ही निवेश किया जा सकेगा। क्रिजैक लिमिटेड का यह

विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का अधिग्रहण करना चाहती है एनएमडीसी: सीएमडी

एजेंसी

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की लौह अयस्क उत्पाक एनएमडीसी महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के अपतटीय अधिग्रहण का ब्लॉक रूप से चयनित करने का रही है। कंपनी के मूल्यमय एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमिताव मुखर्जी ने कहा कि इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में कंपनी की उपस्थिति मजबूत होगी। एटीएम, लिथियम, कोबाल्ट, तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिज सौर पैनल, पवन चक्की, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए जरूरी हैं। भारत ने उनकी दीर्घकालिक उपलब्धता और प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को

एन्सीएमएम) शुरू किया है। मुखर्जी ने कहा, अपनी वैश्विक खनिज विविधिकरण रणनीति के तहत, एन्सीएमडीसी वैश्विक स्तर पर 10 रणनीतिक खनिज परिसंपत्तियों में अधिग्रहण के अवसरों का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रही है। एम्पायसीडीसी वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रही है। ब्रज बर्ड में एम्पायसीडीसी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि एम्पायसीडीसी वैश्विक अवसरों का प्रवेश द्वार है और अन्य कार्यालय, कंपनी के खनन परिदृश्य को दोबारा परिभाषित करने के लिए तैयार है।

सर्पा बाजार में लौटी तेजी,
एजेंसी

नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का सामना करने के बाद आज घरेलू सर्राफा बाजार में जोरदार तेजी नजर आ रही है। सोना आज 920 रुपये से लेकर 1 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में भी आज 3 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। भाव में तेजी आने की वजह से आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 98,410 रुपये से लेकर 98,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 90,210 रुपये से लेकर 90,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच चला रहा है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी आने की वजह से ये



चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,17,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 98,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 90,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 98,410 रुपये

सोना और चांदी की बढ़ी चमक



कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 98,410 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 98,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 90,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 90,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 98,560 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक एवं सम्पादक हरिनाथ सिंह द्वारा टिनटिन प्रिन्टेड प्राइवेट लिमिटेड डी-33 अगोसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, नादरगंज, लखनऊ से मुद्रित एवं 1/39 प्रथम तल करामत मार्केट निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित, सम्पर्क-522-4064242
Email: noidarp@gmail.com, therptimes@yahoo.com, 9918735329 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

सूचना पाठकों को सुझाव दिया जाता है, कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले स्वयं उचित जाँच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावे की साई का आशवासन नहीं देता तथा ऐसे विज्ञापनों पर विश्वास करके किसी भी व्यक्ति को हई क्षति, हानि, परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
